



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, १८ मार्च, १९९६/२८ फाल्गुन, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८(३) के अन्तर्गत इस विभाग की अधिसूचना संख्या अम (ए) ४-२७/९३-II, दिनांक २८-२-१९९६ की अधिकृत का हिन्दी अनुवाद ।

अम विभाग

अधिसूचना

शिमला-१७१००२, २८ फरवरी, १९९६

संख्या अम (ए) ४-२७/९३-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दर पुनरीक्षित कर दी जाए :—

१. सड़क निर्माण या अनुरक्षण तथा भवन क्रिया
२. पत्थर तुड़ाई या पत्थर कृषिग
३. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट

4. वन एवं ाष्ठ क्रिया
5. रसायन तथा रासायनिक उत्पाद
6. दुकानें तथा वाणिज्य संस्थान
7. इंजीनियरिंग उद्योग
8. खाद्य एवं पेय पदार्थ
9. गलीचा व शाल बुनाई
10. वस्त्र एवं होजरी उद्योग
11. कागज उत्पाद
12. ईंट भट्ठा उद्योग
13. ल डी पर आधारित तथा फर्नीचर उद्योग
14. त्रिनिर्माण प्रक्रिया जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (के) में प्रभावित हो
15. मद्य निर्माण शालाओं शराब कारखानों और अन्य अनुसूचित प्रचालनों जैसे बोतल भरना
16. सीमेंट कारखानों तथा सीमेंट से बनने वाले अन्य उत्पद
17. आरा मशीन
18. निजी शैक्षणिक संस्थानों
19. कास्टिंग उद्योग
20. चमड़ा उद्योग
21. इलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज
22. होटल रेस्टोरेट

2. और यतः राज्य सरकार को उपरोक्त नियोजनों में कार्यरत अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरों को पुनरीक्षित करने के विषय में सलाह देने के लिए एक समिति अधिसूचना संख्या 27-1/90-थम, तारीख 9-2-1996 द्वारा गठित की गई थी।

3. और जबकि वरिष्ठ समिति ने अपनी सिफारिशें हिमाचल प्रदेश सरकार को 22-2-1996 को प्रस्तुत कर दी हैं।

4. अतः अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी, धन समिति द्वारा की गई सलाह और सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि और चाय बागानों में नियोजन के अलावा, ऊपर वर्णित 22 अनुसूचित नियोजनों के सभी अनुसूचित नियोजनों में अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरें 26/- रुपये प्रतिदिन या 780/- रुपये प्रतिमास से 45.75 रुपये प्रतिदिन या 1373/- रुपये प्रतिमास पुनरीक्षित करने हैं।

5. यह कि दकानों, वाणिज्य संस्थानों, होटलों और रेस्टोरेट, में नियोजित अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की अनुपातिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों आदि के मूल्य में भी उसी अनुपात में 142/- रुपये प्रतिमास से 250/- रु० प्रतिमास वृद्धि होगी।

6. यह कि पुनरीक्षित दरें सभी भत्तों के सहित है।

7. यह कि पुरुष तथा महिला मजदूरों की न्यूनतम दरों में कोई भिन्नता नहीं होगी।

8. यह कि अप्रेंटिसों/प्रशिक्षार्थियों की मजदूरी अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के अधीन विनियमित की जानी है।

9. यह कि कुमारों और बान कर्मचारों की मजदूरी प्रौढ़ कर्मचारों के समान होगी।

10. यह कि मजदूरी की दरें 1 मार्च, 1996 से प्रभावी होंगी।

आदेश द्वारा,

एम०एस० मिश्र.

वित्तियुक्त एवं सचिव।